रेलवे द्वारा भारत से बाहर किया गया निर्माण कार्य

2539. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विदेशों में भी निर्माण कार्य करता है, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में किए गए निर्माण कार्य का देशवार मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि अनेक देशों ने कार्य घटिया दर्जे होने की शिकायतें की हैं, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उन देशों के नाम क्या हैं जिनके ऐसी शिकायतें मिली हैं और उस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (इरकान) जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कम्पनी है, विदेशों में निर्माण कार्य करती है । विगत 3 वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा विदेशों में निष्पादित किये गये निर्माण-कार्यों के मूल्य का देश वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

देश	मूल्य
इराक	490 करोड़ रुपये (लगभग)
अल्जीरिया	116 करोड़ रुपये (लगभग)
सऊदी अरब	20 करोड़ रुपये (लगभग
नाइजीरिया	0.56 करोड़ रुपये (लगभग

(ख) जी नहीं ।

विश्व बैंक के सहयोग से चल रही रेलवे परियोजनाएं

2540. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों में विश्व बैंक के सहयोग से चल रही रेलवे परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और ये परियोजनाएं किस-किस तारीख को आरम्भ की गई थीं ;

(ख) उनको पूरा करने के लिए कितनी समयावधि नियत की गई है ;

(ग) निर्माण कार्य में मरने वाले तथा घायल होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(घ) मुआवजे के रूप में उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) विश्व बैंक से प्राप्त वर्तमान क्रेडिट/ऋणों के अन्तर्गत चल रही रेल परियोजनाओं का अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) दिसम्बर, 1978 में तय किया गया 190 मिलियन डालर का क्रेडिट 844 आई एन :

विश्व बैंक के इस क्रेडिट के अन्तर्गत पहिया एवं धुरा संयंत्र, चार कारखानों यथा माटुंगो, परेल, कंचरापाड़ा और खड़गपुर तथा चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के आधुनिकीकरण, पहियों एवं धुरों, रेल इंजनों के पुर्जों तथा अन्य छोटी-मोटी मदों की खरीद के लिए सहायता प्राप्त है ।

पहिया एवं धुरा संयंत्र पर लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत आने का अनमान लगाया गया है और इसमें उत्पादन शुरू हो गया है ।

कारखानों के आधुनिककीकरण पर लगभग 65 करोड़ रुपये की लागत आने का अनमान है और यह काम चालू वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ii) अक्तूबर, 1982 में तय किया गया 400 मिलियन डालर का आई डी० ए० क्रेडिट 1299/ऋण 2210 आई एन :

विश्व बैंक के इस क्रेडिट/ऋण के अन्तर्गत डीजल पुर्जा कारखाना (डी सी डब्ल्यू) पटियाला, माल डिब्बों के लिए

पुर्जों, उच्च अश्वशक्ति वाले बिजली रेल इंजनों, पहियों एवं धुरों, रेल इंजनों के पुर्जों तथा अन्य छोटी-मोटी मदों की खरीद के लिए सहायता प्राप्त है।

डी० पु० का०/पटियाला पर लगभग 133 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है और यह कार्य सातवीं योजना में पूरा हो जाने की संभावना है।

(iii) मई, 1984 में तय किया गया 280 मिलियन डालर का ऋण:

इस ऋण के अन्तर्गत 3044 मार्ग कि० मी० विद्युतीकरण तथा 6 कारखानों और सवारी डिब्बा कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्राप्त है।

विश्व बैंक ने जिन खंडों के विद्युतीकरण के लिए ऋण दिया है, उन पर लगभग 680 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। 6 कारखानों तथा सवारी डिब्बा कारखाने के आधुनिकीकरण पर लगभग 162 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। कारखानों के आधुनिकीकरण का काम सातवीं योजना में पूरा हो जाने की सम्भावना है। विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य तिथियां निर्धारित नहीं की गयी हैं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बसों तथा ट्रकों के परमिटों का जारी किया जाना

2541. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को बसों और ट्रकों के कितने अन्तर्राज्यीय परमिट जारी किए और ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परमिटों के आवंटन में घपला करने के लिए अनेक अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराई गई थी, यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) केन्द्रीय सरकार, समय समय पर धारा 63(11) के तहत पब्लिक कैरियरों के लिए राष्ट्रीय परमिटों और धारा 63(7) के तहत यात्री वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों की संख्या निर्दिष्ट करती है। हर वर्ष आवंटन नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवंटन और राज्य सरकारों द्वारा इन श्रेणियों के परमिटों के अब तक किए गए आवंटन का विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से सूचना एकत्र की की जा रही है ?

विवरण

31 जुलाई, 1985 को केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 63 (11) के तहत पब्लिक कैरियरों के लिए राज्य सरकारों को अब तक आवंटित किए गए राष्ट्रीय परमिट धारा 63 (7) के तहत यात्री वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आवंटित राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या	जारी राष्ट्रीय परमिटों की कुल संख्या	ओम्नी बसों के लिए आवंटित अखिल भारतीय पयटक परमिटों की कुल संख्या	ओम्नी बसों के जारी अखिल भारतीय पर्यटक परमिटों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	1650	1350	50	50+2+